सियासत की भेंट चढ़ रहा चीनी उद्योग

» चुनावी साल में गन्ना किसानों को लुभाने की राजनीतिक दलों में होड़

» रंगराजन फार्मूला लागू कर तय किया जाए गन्ना मूल्य : इस्मा

» चीनी मिलों का बढ़ेगा घाटा, भुगतान न होने से गन्ना किसान भी रहेगा तंग

चीनी का गणित

2011-12 में चीनी मूल्य
₹31.50 प्रति किलो

2012-13 में मूल्य घटकर
₹29.50 प्रति किलो

हो सकता है एरियर
₹13,000 करोड़

उप्र की मिलों को हो सकता है घाटा
₹10,000 करोड़

चीनी उद्योग की मांग

- गन्ना मूल्य को चीनी मूल्य से जोड़ा जाए
- चीनी मूल्य का 75 फीसद हिस्सा किसानों को गन्ना मूल्य के रूप में मिले
- तीन फीसद के सोसाइटी कमीशन में छूट दी जाए
- बैंकों के कर्ज पर मिलों को ब्याज सब्सिडी मिले

खास बातें

- महाराष्ट्र में चीनी की रिकवरी दर ज्यादा, गन्ना मूल्य कम
- उत्तर प्रदेश में कम रिकवरी दर पर गन्ना मूल्य ज्यादा
- मिलें सांसत में, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ठोस पहल नहीं
- गन्ना मूल्य घोषित किए बगैर पेराई शुरू करने का दबाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घाटे के दलदल में छटपटा रहा चीनी उद्योग चालू चुनावी साल में सियासत की भेंट चढ़ सकता है। सरकार की नीतियों के कारण चीनी मिल मालिक परेशान हैं। चीनी उद्योग को आधा अधूरा नियंत्रणमुक्त करने की वजह से उनकी मुश्किलें और भी गंभीर हो गई हैं। चीनी की उत्पादन लागत बढ़ी है। वहीं, खुले बाजार में चीनी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले तेजी से कम हुई हैं। लिहाजा घाटा उठा रहीं मिलों के लिए इस बार पेराई शुरू कर पाना भारी लगने लगा है। चुनावी साल में गन्ने को लेकर शुरू हुई सियासत भी चीनी उद्योग पर भारी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) घोषित किए बिना ही मिलों को चलाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में मिलों के लिए गन्ने का पूरा भुगतान करना संभव नहीं होगा। एरियर बढ़ने से राज्य की चुनावी राजनीति पर उल्टा असर पड़ना तय है। राज्य सरकार के साथ हुई चीनी उद्योग संघ की बैठक नाकाम साबित हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना वाले गढ़ में डगमगाती अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की मुश्किलें और भी हैं। गन्ने का ऊंचा मूल्य उनकी पहले से खराब वित्तीय हालत को और बदतर कर रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें दोहरी मार से गुजर रही हैं। महाराष्ट्र में चीनी की रिकवरी दर ज्यादा होने के बावजूद गन्ना मूल्य कम है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका उलटा है। मिल मालिकों को आशंका है कि मूल्य न भी बढ़े तो भी पिछले एसएपी पर चीनी उद्योग को 10 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना एरियर के रूप में 2,400 करोड़ रुपये का बकाया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा सरकार के रुख से खासा नाराज हैं। वह गन्ना मूल्य निर्धारण में रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को लागू कराना चाहते है। इसके मुताबिक गन्ना मूल्य को चीनी कीमतों से सीधे जोड़ दिया जाना चाहिए। यानी चीनी मूल्य का 75 फीसद गन्ना मूल्य के रूप में दिया जाए। चीनी उद्योग का कहना है कि ऐसा होने के बाद ही गन्ने की पेराई शुरू की जा सकती है। उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिलों में तय तारीख से पेराई शुरू कराने को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। संबंधित खबर पृष्ठ »7

किसान संगठनों को एतराज

जहां तक किसान संगठनों का सवाल है तो वे भी पेराई समय से शुरू कराने के हक में हैं। लेकिन इस्मा के फार्मूले पर उन्हें एतराज है। किसान जागृति मंच के संयोजक सुधीर पंवार का कहना है कि किसान बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव को सहन नहीं कर सकता है। उन्हें रंगराजन फार्मूले पर भी आपत्ति है। उनका कहना है कि चीनी बनाने में 12 फीसद की लागत आती है, फिर मिलें अतिरिक्त 13 फीसद का फायदा क्यों चाहती हैं। अलबत्ता किसान नेता चाहते हैं कि सरकार को मिलें चलाने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। चीनी उद्योग पर केंद्र की ओर से लगे नियंत्रण तो हटा लिए गए हैं, लेकिन एसएपी घोषित करने का राज्य सरकारों का अधिकार बना हुआ है।

Dainik Jagaran.
18/11/13